भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)
COMMUNIST PARTY OF INDIA (MAOIST)
केन्द्रीय कमेंटी

30 जनवरी 2021 प्रेस विज्ञप्ती

मोदी सरकार के जन विरोधी तीनों कृषि कानून पूरी तरह रद्द करने तक संघर्ष जारी रखो!

दिल्ली एवं देशभर में एकता और दृढ़संकल्प के साथ, मोदी सरकार के किसान विरोधी तीन कानूनों को रद्द करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे किसानों को, फिर एक बार भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए लाल सलाम पेश करती हैं। हम किसानों के 26 जनवरी के ''ट्रैक्टर परेड रैली'' का पुरजोर और गर्मजोशी से स्वागत करते हैं।

दिल्ली और देशभर में चल रहे इन किसान आंदोलनों ने ब्रिटिशों के रौलट ॲक्ट के विरोध की याद ताजा कर दी। तब ब्रिटीश थे आज साम्राज्यवादी दलाल मोदी हैं। तब भगतसिंह थे आज संग्रामी किसानों के रूप में उनके लाखों वारिस हैं। सरकार कानून वापस लेने के बजाय समय बिताकर आंदोलन को पस्त करने की नीति अपना रही हैं। बातचीत 11 दौर हुए और हर दौर में किसान नेताओं ने स्पष्ट रूप से कानून रद्द करने की मांग ही प्रमुख रूप से कहने के बावजूद सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाया। क्योंकि सरकार साम्राज्यवादी और भारत की दलाल कंपनीयों की सरकार है।

लाखों किसानों ने ट्रैक्टरों द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली कूच करके दुनिया को यह दिखा दिया कि यह गणतंत्र कैसा पक्षपाति एवं किसान विरोधी हैं। रैली को अनुमती देने के बाद भी सरकार ने पुलिस द्वारा किसानों को रोकने की हर संभव कोशिश की। किसानों के मार्ग में जानबूझकर बैरिकेट्स लगाए। आँसू गैस छोड़े। लाठीचार्ज किया। एक नवरीत सिंह नाम के नौजवान की मृत्यु भी हुई। कानून और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती हैं। किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए सरकार ने भरसक कोशिशें की। मोदी सरकार की पहले से ही यह कोशिशें रही हैं कि इस आंदोलन में घुसकर भेद और गड़बड़ियाँ पैदा करें। 26 जनवरी को हुई हिंसक वारदातों के पीछे स्पष्ट रूप से सरकार का ही हाथ रहा है। दीप सिधू और लख्खा सिधना इन भाजपा के एजेंटो को आंदोलन को भटकाने के लिए घुसाया गया। विशेष सुरक्षा के बावजूद इन एजेंटो को लाल किले के तरफ बढ़ने दिया। लाल किले पर झंडा लगाना, ट्रैक्टर रैली को हिंसक रंग देना और फिर किसान नेताओं पर झूठे केसेस दाखिल करना यह ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी मोदी सरकार के षड़यंत्रकारी प्लान का हिस्सा है। सरकार की इस घटिया और निरंकुश हरकत की हम घोर निंदा करते हैं। हम पुलिस और सेना के जवानों से अपील करते हैं कि वे संयम रखे और किसानों के समर्थन में खड़े हो जाए क्योंकि वे भी किसानों के ही बेटे, बेटीयाँ हैं।

लाल किले से प्रधान सेवक होने का दंभ भरने वाले पाखंडी जुमलेबाज प्रधानमंत्री का इस रैली ने पर्दाफाश कर दिया। नरेन्द्र मोदी देश की जनता का प्रधान सेवक नही बल्कि साम्राज्यवादीयों का और दलाल कार्पोरेट घरानों का प्रधान सेवक हैं यह सत्य अब खुलकर सामने आया है। कानून रद्द करने के अलावा कुछ भी मान्य नहीं, यह दृढ़संकल्प अपनी एकता के माध्यम से दिखाकर, समझौता करने की चालबाजियों को आपने धूल चटाई। किसानों के संयुक्त मंच के बाहर अभी भी कुछ शक्तियाँ हैं। उनको हम अपील करते हैं कि वे इस वक्त की आवश्यकता को समझे और इन कानूनों को रद्द करने की इस लड़ाई को मिलकर लड़े।

मोदी सरकार खाद्यान्न भंडार अदानी और अंबानी के हवालें कर गरीब जनता के मुहँ का निवाला छीन रही है। निजी मंडियाँ खोलकर और जमीन कार्पोरेट के हाथों में सौंपकर किसानों की गर्दन पर कार्पोरेट शिकंजा कसा जा रहा है। छोटे धंधो और व्यापारियों के आजीविका के साधन छिनने का फर्मान ही ये कानून हैं। इन कानूनों से न केवल किसान बल्कि आम जनता का 80 प्रतिशत हिस्सा बुरी तरह प्रभावित होने वाला है। इसलिए हम तमाम जनता से अपील करते हैं कि किसानों के संघर्ष में शामिल हो जाए। उनके समर्थन में देशभर में अपने–अपने क्षेत्र में सतत संघर्ष करें। और मोदी सरकार को यह कानून वापस लेने के लिए मजबूर करें। किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित 1 फरवरी, 2021 का संसद घेराव और संघर्ष के अन्य कार्यक्रमों के समर्थन में देशभर में निदर्शन और प्रदर्शन करने की तमाम जनता को हम अपील करते हैं। माओवादी पार्टी श्रेणी, पीएलजीए, तमाम क्रांतिकारी जनसंगठन, जनसंगठन और जनताना सरकार को आह्वान है कि वे देश में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में और तीनों कृषि संबधित कानूनों को रद्द करने के लिए सतत संघर्ष जारी रखें। इसी संघर्ष की कड़ी के रूप में 10 फरवरी 2021 को(महान भूमकाल संघर्ष के दिन) देशभर में प्रदर्शन करें।

अभय

अभय

प्रवक्ता,

केंद्रीय कमेटी,

भाकपा (माओवादी)